expansion may have caused some buoyancy in the general price level.

(c) and (d) The average annual inflation rate based on wholesale price index between 1981 to 1990 was 7.2% compared to 9.6% in the preceding decade. (*i.e.* 1970—80).

(e) to (g) A number of anti-inflationary measures were initiated by the Government to dampen the inflationary pressures. Improved supply management in essential commodities has been successfully accomplished by way of open markets sale of foodgrains by FCI, import of nearly one million tonnes of sugar for PDS. Edible Oil price has been kept stable through timely imports for PDS. Shortfall in domestic cotton production was made up by permitting duty free import of cotton.

Government is striving to limit the fiscal deficit for 1994-95 to 6% of GDP as against 7.3% (RE) last year.

Merger of New Bank of India with P.N.B.

969. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that after merger of the New Bank of India with the Punjab National Bank certain anomalies have cropped up, such as (i) arbitrary change of gratuity criteria, resulting in financial loss; (ii) arbitrary reduction in the age of retirement of officers; (iii) loss of seniority in many cases ; (iv) reduction of several perks that were available to the erstwhile employees of the New Bank of India; and

(b) if so, what directions are given or would be given so that the employees of the erstwhile New Bank of India are not put to undue harm ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY) : (a) and (b) Punjab National Bank (PNB) has reported that in accordance with the provisions contained in Clause 3(3) and 5 (2) of the New Bank of India (Amalagamation and Transfer of Undertakings) Scheme, 1993, it has, with the approval of its Board of Directors, made some changes in the terms and conditions of service of the officers and other employees belonging to Erstwhile New Bank of India (ENBI) on their absorption in PNB for the purpose of maintaining uniformity amongst officers and employees of the bank as a whole. While doing so, certain benefits available to the employees of ENBI could not be protected on their absorption in PNB because similar benefits were not available to the employees of PNB at the relevant time. The Bank has further reported that some employees of ENBI aggrieved by the decision of PNB, have filed petitions in High Courts at different places and as such, the matter is subjudice.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण

970. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु सड़क परिवहन परिचालकों को शत-प्रतिशत वित्त सहायता दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में इस संबंध में लाभान्वित होने वाले परिचालकों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(ग) इस सुविधा को प्राप्त करने के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी) लघु सड़क परिवहन परिचालकों (एस आर टी ओ) को शत-प्रतिशत पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। उधारकर्ताओं को वाहन की कम से कम 15 प्रतिशत लागत वहन करनी होती है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसी लागत का 85 प्रतिशत अथवा उससे कम ही उपलब्ध कराते हैं। तथापि, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) लघु सड़क परिवहन परिचालकों को मंजूर किए जाने वाले ऋण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 100 प्रतिशत पुनर्वित सुविधा उपलब्ध कराता है।

(ख) वर्ष 1993-94 (राज्य वार) के दौरान नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता से आरआरबी द्वारा वित्तपोषित एस आर टी ओ एककों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :-असम-55, मिजोरम-30 बिहार-11, उड़ीसा-56, पश्चिम बंगाल-2, मध्य प्रदेश-30, हरियाणा-101, हिमाचल प्रदेश-61, जम्मू एवं कश्मीर-15. पंजाब-1 राजस्थान-15, उत्तर प्रदेश-19, गुजरात-118, महाराष्ट्र-21, आन्ध्र प्रदेश-35, कर्नाटक-171, केरल-44 और तमिलनाडु-2

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि योजना के अन्तर्गत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित सहायता स्वतः आधार पर उपलब्ध कराई जाती है और नाबार्ड वित्त पोषित बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर विश्वास करता है। बैंकों को प्रस्तावों की वित्तीय अर्थक्षमता और उद्देश्य की प्रमाणिकता, उधारकर्ताओं की ऋण साख आदि के बारे में अपने आप को संतुष्ट करना होता है। आवेदन पर आवश्यक प्रक्रिया के बाद, बैंक द्वारा ऋण मंजूर किया जाता है, ऋण का संवितरण उधारकर्ता द्वारा आवश्यक ऋण दस्तावेजों के पूरा करने के बाद ही किया जाता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वसूल की गई बकाया राशि

971. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने वाली एककों से बकाया के रूप में एक बड़ी राशि वसूल की जानी है ;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 93 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार स्थिति क्या है और वह राशि कुल ऋण की कितने प्रतिशत है ;

(ग) सरकार ने बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए क्या प्रयास किये हैं ; और

(घ) इस संबंध में शीघ्र वसूली हेतु और न्यायिक कार्यवाही हेतु क्या प्रयास किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विभिन्न योजनाओं में जमा राशि

972. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की योजनाओं, राष्ट्रीय बचत योजनाओं और विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि का योजना-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) किन-किन वित्तीय संस्थाओं ने गुजरात सरकार को वित्तीय सहायता दी है और उक्त सहायता किन शर्तों पर दी गई है ?